30 सितम्बर, 2014

थिलावा: म्यांमार के प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र का महत्व

*डॉ. राहुल मिश्रा **

परिचय

म्यांमार तेजी से आर्थिक आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। संशोधित निवेश कानून, सुधार उपायों की श्रृंखला और देश के राजनीतिक, मीडिया और आर्थिक क्षेत्रों के खुलने से देश तेजी से बदल रहा है। म्यांमार, जो वैश्विक मुख्यधारा से हटकर एक अलग अर्थव्यवस्था है, अब निर्यात-उन्मुख विकास सूत्र को अपना रहा है, जिसका अनुसरण कई अन्य एसोसिएशन ऑफ साउथ-ईस्ट एशियन नेशन्स (आसियान) देशों ने किया है। इस संबंध में एक उल्लेखनीय उदाहरण हैथिलावा, जोदेश का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) है और जिसे यांगून के बाहरी इलाके में बनाया जा रहा है। यह जापानी सरकार, तीन जापानी कंपनियों (मारूबेनी, मित्सुबिशी और सुमितोमो) और म्यांमार सरकार का एक संघ है। थिलावा म्यांमार में सबसे बड़ी जापानी निवेश परियोजना भी है। म्यांमार-जापान थिलावा डेवलपमेंट (एमजेटीडी) का मालिकाना हक 49 प्रतिशत है, जिसमें मारुबेनी, मित्सुबिशी और सुमितोमो और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की संयुक्त हिस्सेसदारी है। थिलावा को अगली पीढ़ी के एसईजेड के रूप में माना जाता है। यंगून के आस-पास होने के कारण, एसईजेड को एक विशाल बाजार तक आसानी से पहुंच प्राप्त होगी। हालांकि, इसका दूसरा पहलू यह है कि इसके नदी पर बंदरगाह बड़े जहाजों को संभालने में सक्षम नहीं होगा, जिससे थिलावा में और उससे बाहर वस्तुओं के तेजी से आवागमन बाधितहो सकता है।

22 सितंबर, 2014 को, म्यांमार थिलावा एसईजेड होल्डिंग्स (एमटीएसएच) के अध्यक्ष विन औंग ने घोषणा की कि थिलावा स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के शेयरों को ओवर-द-काउंटर स्टॉक मार्केट के माध्यम से बेचा जाएगा। बैंकाक पोस्ट की रिपोर्ट (23 सितंबर, 2014) के अनुसार,2015में स्टॉक एक्सचेंज की शुरूआत पहले कर देने सेशेयर 2014 के अंत में उपलब्ध होंगे। यह म्यांमार में कंपनियों के कामकाज में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि चीन, सिंगापुर और अमेरिका सहित अठारह विदेशी कंपनियों ने थिलावा में निवेश करने के इच्छुक हैं, और उनके निवेश से परियोजनाएं2015 तक पूरी तरह से चालू हो जाएंगी। रिपोर्टों के अनुसार, पहले चरण में यूएस $ 180मिलियन की लागत का अनुमान है और लगभग यूएस $ 50 मिलियन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निवेश पहले ही किया गया है।

चीन का घटता दबदबा

चूंकि म्यांमार स्वयं द्वाराअधिरोपित अलगाव से बाहर निकल रहा है और थीन सीन सरकार सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, कई देशों ने एक बार परित्याग किए गए राष्ट्र (म्यांमार) में भारी निवेश करना शुरू कर दिया है। इन सभी देशों में, चीन म्यांमार का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और साथ ही देश का सबसे बड़ा निवेशक भी रहा है। वास्तव में, म्यांमार के स्वयं के अलगाव की अवधि के दौरान, चीन उसका सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक भागीदार के रूप में था। हालाँकि, स्थिति धीरे-धीरे बदल रही है, और म्यांमार देश ने अपने विदेशी और आर्थिक संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत की है। हाल के रुझानों से पता चलता है कि म्यांमार अपने व्यापार सहयोगियों और निवेश के स्रोतों में विविधता लाकर चीन पर अपने आर्थिक निर्भरता को कम करने का प्रयास कर रहा है।

इसे आंशिक रूप से,स्थानीय रूप से तथा चीन के म्यांमार में वित्त पोषित परियोजनाओं, जैसे कि मित्सितोन बांध, लेटपडांग कॉपर माइनमें, और हाल ही में दक्षिणी शान राज्य के कुन्हिंग टाउनशिप में 7,000-मेगावाट केहाइड्रोपावर बांध एक ठोस विरोध कहा जा सकता है। स्पष्ट रूप से, चीन की संसाधन कूटनीतिम्यांमार में बैकफ़ायर करने लगी है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले तीन वर्षों में देश में चीनी निवेश काफी हद तक घट गया है। उदाहरण के लिए, जबकि 2008 में, चीन ने म्यांमार में यूएसएस $ 12 बिलियन का निवेश किया था, मगर 2012-2013 में निवेश सिर्फ 407 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक सिकुड़ गया।

हालांकि म्यांमार में चीनी निवेश कम हो रहा है, लेकिन अपने आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की शुरुआत के साथ, म्यांमार ने कई अन्य निवेशक देशों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। हाल ही में, जापान ने म्यांमार में भारी निवेश किया है। उल्लेखनीय है कि जापान म्यांमार का सबसे बड़ा सहायता दाता रहा है। 2014 की शुरुआत में, जापान ने ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस (ओडीए) के ढांचे के तहत म्यांमार में संघर्षरत क्षेत्रों के लिए मुख्य रूप से यूएस $ 96 मिलियन प्रदान करने का वादा किया।

अब, जापान कई पहलों के माध्यम से म्यांमार में अपने निवेश को आगे बढ़ा रहा है। उदाहरण के लिए, 15 दिसंबर 2013कोटोक्यो में राष्ट्रपति यू थीन सीन और जापानी प्रधानमंत्री, शिंजो आबे द्वारा उदारीकरण, संवर्धन और निवेश के संरक्षण के लिए एक निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते का प्राथमिक उद्देश्य जापानी निवेशकों के लिए अनुकूल निवेश माहौल बनाकर म्यांमार में जापानी निवेश के प्रवाह को बढ़ाना था। समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ, आबे ने न केवल म्यांमार को 5.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण चुकाने से मुक्ति दी, बल्कि म्यांमार देश में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए और सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया।

म्यांमार में जापान की गहरी अभिरुचि

जापान द्वारा वित्तपोषित सभी अवसंरचना परियोजनाओं में से, थिलावा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे उल्लेखनीय है। यांगून से 23 कि.मी. दूर स्थित, म्यांमार में यह जापान की सबसे बड़ी निवेश परियोजना है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) इस 5,900 एकड़ के आर्थिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए म्यांमार सरकार, म्यांमार की कंपनियों और जापानी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। म्यांमार सरकार और म्यांमार में स्थानीय संस्थाओं द्वारा 51 प्रतिशत पूंजी प्रदान की जाने की सूचना है और शेष पूंजी तीन उपर्युक्त जापानी कंपनियों के सहयोग से जापानी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार, म्यांमार परियोजना में बड़ा हितधारक है।

एक बार चालू हो जाने के बाद, यह दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में निर्मित अपने आपे में पहला ऐसा औद्योगिक पार्क बनने जा रहा है। अन्य बातों के अलावा, थिलावा एसईजेड में खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों, कपड़ा कारखानों और स्पेयर पार्ट्स फर्मों को स्थापित किया जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार, वित्तीय, बीमा और चिकित्सा सेवा क्षेत्रों, हल्के उद्योगों (श्रम-गहन लेकिन गैर पारंपरिक क्षेत्र), रसद और परिवहन क्षेत्रों, न्यू टाउनशिप और वाणिज्यिक क्षेत्रों, आर एंड डी, ऊष्मायन, और व्यावसायिक प्रशिक्षण थिलावा के प्रमुख घटक बनने की संभावना है।

इसके अलावा, चूंकि यह म्यांमार के वित्तीय केंद्र यांगून के बहुत करीब स्थित है, इसलिए यह अन्य एसईजेड की तुलना में एक बड़ा उपभोक्ता-उन्मुख बाजार होने जा रहा है। जापान के लिए, थिलावा परियोजना का पूरा होना इसलिए महत्वपूर्ण है कि जापान एशिया में किसी अन्य परियोजना के साथ आगे बढ़ने से पहले,दावी एसईजेड सहित थिलावा एसईजेड के निर्माण को पूरा करना चाहता है।2011 में, थाईलैंड और म्यांमार की सरकारों ने जापान को दावी एसईजेड में रणनीतिक भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया। भारत भी दावी परियोजना में एक हितधारक है।

कयास लगाए जा रहे हैं कि जापान थिलावा एसईजेड को बढ़ावा दे रहा है ताकि म्यांमार में चीन के आर्थिक और रणनीतिक दबदबे का मुकाबला किया जा सके। हालांकिकिसी परियोजना में निहित रणनीतिक अनुमानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, यह भी स्पष्ट है कि म्यांमार और जापान दोनों के पास थिलावा एसईजेड में कार्य करने के लिए अपने स्वयं के कारण और तर्क हैं। फिर भी, कुछ लोगों का तर्क है कि चीन म्यांमार में जापान की आर्थिक कूटनीति में प्रमुखता से काम कर रहा है।

सुस्त अर्थव्यवस्था और जातीय संघर्ष जैसी समस्याओं से जूझ रहे म्यांमार को अपनी आर्थिक स्थिरता के लिए विविध स्रोतों से विदेशी निवेश की सख्त जरूरत है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि70 प्रतिशत आबादी के पास अभी भी बिजली की सुविधा नहीं है। इसके अलावा, ऐसी स्थिति में जब म्यांमार किसी एक देश पर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करने का प्रयास

कर रहा है, तब जापान सबसे अधिक विकल्प के रूप में प्रतीत होता है। म्यांमार में बढ़ते व्यापारिक अवसरों के कारण, जापान के लिए म्यांमार निवेश की संभावनाओं के संबंध में सबसे अनुकूल विदेशी स्थलों में से एक है। थिलावा एसईजेड को विकसित करने और म्यांमार में भारी निवेश करके, जापान का लक्ष्य है कि वह म्यांमार में और संभवत: आने वाले वर्षों में व्यापक दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में एक बड़ा घटक स्थापित हो सके। इससे ऐतिहासिक व्यापारिक परियोजना'थिलावा'रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण परियोजना भी है। स्पष्ट रूप से, थिलावा परियोजना, यदि यह अपने लक्ष्यों को पूरा करती है, तो म्यांमार में जापानी गतिविधि और निवेश के नए आयाम खुलेंगे, जिससे भारत सहित अन्य प्रमुख हितधारकों के अनुकरण हेतु एक उदाहरण स्थापित होगा।

*****

*डॉ. राहुल मिश्रा, भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली में अध्येता हैं

*

अस्वीकरण: व्यक्त मंतव्य लेखक के हैं और परिषद के मंतव्यों को परिलक्षित नहीं करते।